गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 247
दि. 07.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राजनीतिक उतार-चढ़ाव, सामाजिक न्याय और सत्ता की लंबी पारी: सिद्धारमैया ने रचा कर्नाटक का नया इतिहास

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक ऐसा अध्याय दर्ज हो चुका है, जिसने सत्ता के आंकड़ों से आगे जाकर राजनीतिक धैर्य, वैचारिक लचीलापन और सामाजिक न्याय की दीर्घ साधना को नई परिभाषा दी है। सिद्धारमैया अब राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हो चुके हैं। अपने दो कार्यकालों को मिलाकर उन्होंने 2,792 दिनों का सफर तय किया है और 7 जनवरी के बाद यह रिकॉर्ड पूरी तरह उनके नाम दर्ज हो जाएगा। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने मैसूर के ही दिग्गज नेता देवराज उर्स की बराबरी करते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है। यह केवल दिनों की गणना नहीं, बल्कि कर्नाटक की सामाजिक और राजनीतिक चेतना के बदलते स्वरूप की कहानी भी है।

देवराज उर्स को कर्नाटक में सामाजिक न्याय, भूमि सुधार और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक ताकत देने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है। उसी परंपरा में सिद्धारमैया को भी देखा जाता है, जिन्होंने खुद को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के पक्षधर नेता के रूप में स्थापित किया। उर्स के बाद वह दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राज्य में पांच साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया और फिर दोबारा सत्ता में लौटकर इतिहास रच दिया। 2013 से 2018 तक उनका पहला कार्यकाल 1,829 दिनों का रहा, जबकि मई 2023 में शुरू हुए दूसरे कार्यकाल ने उन्हें इस शिखर तक पहुंचाया।

सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा सीधी और सरल नहीं रही। 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर 2005 तक वह कांग्रेस के मुखर आलोचकों में गिने जाते थे। एक गरीब किसान परिवार से निकलकर राजनीति में आए सिद्धारमैया का शुरुआती झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर था। जनता परिवार और लोक दल की राजनीति में उन्होंने खुद को एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन राजनीति में रिश्ते और समीकरण स्थायी नहीं होते। देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडी(एस) से निकाले जाने के बाद वह एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे, जहां उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न थे।

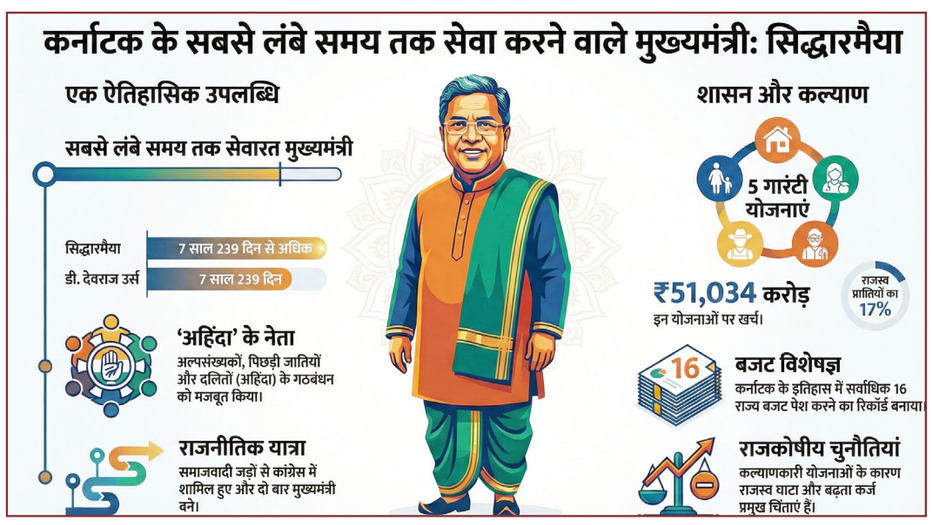

जेडी(एस) से निष्कासन के पीछे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि देवेगौड़ा अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को आगे बढ़ाना चाहते थे और सिद्धारमैया उनकी राह में एक मजबूत चुनौती बनते जा रहे थे। उस दौर में सिद्धारमैया ने राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कही। उन्होंने वकालत में लौटने पर भी विचार किया और एक क्षेत्रीय दल बनाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की विचारधारा से असहमति के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। 2006 में कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए उतना ही बड़ा जोखिम था, जितना उस पार्टी के लिए उन्हें स्वीकार करना।

कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धारमैया ने धीरे-धीरे खुद को पार्टी के भीतर एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया। 2004 के खंडित जनादेश के बाद बनी कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन सरकार में वह उपमुख्यमंत्री बने और एन. धरम सिंह के साथ सरकार चलाई। उस समय उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला होता, लेकिन देवेगौड़ा के हस्तक्षेप ने उनकी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। यही वह क्षण था, जिसने उन्हें पिछड़े वर्गों की राजनीति को नए सिरे से गढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया ने खुद को एएचआईएनडीए—अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित—राजनीति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। एएचआईएनडीए सम्मेलनों के जरिए उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को नई धार दी। यह वही दौर था, जब एचडी कुमारस्वामी को राज्य की राजनीति में उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा था। सिद्धारमैया और देवेगौड़ा परिवार के बीच बढ़ती दूरी ने कर्नाटक की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने खुद को केवल पार्टी नेता नहीं, बल्कि एक जननेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो सत्ता से ज्यादा समाज की बात करता है।

वित्त मंत्री के रूप में उनका अनुभव भी असाधारण रहा। गौड़ा और जे.एच. पटेल दोनों के मंत्रिमंडलों में उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई और कुल 16 बार राज्य का बजट पेश किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो उनकी प्रशासनिक समझ और आर्थिक दृष्टि को दर्शाता है। डॉ. राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित सिद्धारमैया ने राजनीति के लिए अपने वकालत के पेशे को पूरी तरह त्याग दिया। उनके बजट भाषणों में हमेशा सामाजिक कल्याण, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर देखने को मिला।

1983 में लोक दल के टिकट पर मैसूरु की चामुंडेश्वरी सीट से विधायक बनकर विधानसभा में प्रवेश करने वाले सिद्धारमैया ने हार और जीत, दोनों का स्वाद चखा। 1989, 1999 के विधानसभा चुनाव और 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीति में उनकी जिद और प्रतिबद्धता कमजोर नहीं पड़ी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद 2008 के चुनावों में वह पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। हार के बावजूद उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, घोटालों और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर मुखर विपक्ष की भूमिका निभाई।

2013 से 2018 तक का उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल कई मायनों में निर्णायक रहा। प्रशासनिक कुशलता और जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण उन्हें व्यापक लोकप्रियता मिली। हालांकि 2018 के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और सिद्धारमैया खुद चामुंडेश्वरी सीट से जद(एस) के जीटी देवगौड़ा से हार गए। बादामी सीट से जीतकर उन्होंने विधानसभा में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। इसके बाद कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन सरकार की समन्वय समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सरकार गिरने के बाद वह विपक्ष के नेता बने और भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर रहे।

2023 के चुनावों को उन्होंने अपना अंतिम चुनाव बताते हुए वरुणा से मैदान में उतरने का फैसला किया। वहां से मिली जीत ने यह साफ कर दिया कि उनका जनाधार अभी भी मजबूत है। दोबारा मुख्यमंत्री बनते समय उन्होंने संकेत दिए कि यह उनका अंतिम कार्यकाल हो सकता है, लेकिन राजनीति से पूरी तरह दूर जाने का इरादा उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। सत्ता में उनकी वापसी केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति की पुनर्स्थापना भी मानी गई।

आज जब सिद्धारमैया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, तो यह उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस विचारधारा की है, जो सत्ता को समाज परिवर्तन का माध्यम मानती है। उनकी यात्रा बताती है कि राजनीति में धैर्य, विचार और संघर्ष का अपना महत्व होता है। कर्नाटक की राजनीति में यह सिद्धि केवल सत्ता की नहीं, बल्कि विश्वास की भी है।

एआईएडीएमके का आरोप- डीएमके सरकार में भ्रष्टाचार के घोटाले, राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी संघर्ष मंगलवार को एक नए मोड़ पर पहुंच गया जब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के महासचिव एडप्पाडी पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात करने के बाद पलानीस्वामी ने बताया कि 2021 से अब तक कथित भ्रष्टाचार की विस्तृत सूची उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है और मामले की निष्पक्ष, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है।

पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने सरकारी विभागों के माध्यम से लगभग चार लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया। उनके अनुसार, सरकार का प्रशासनिक ढांचा अब जनता के हित के बजाय निजी या व्यावसायिक संस्थाओं के समान काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इन आरोपों को साबित करने के पर्याप्त दस्तावेज और सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकारियों और वित्तीय रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पलानीस्वामी ने बताया कि सरकार हर साल एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है, और इस दौरान राज्य की वित्तीय स्थिरता और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीटीआर की कथित ऑडियो क्लिप में भारी भरकम लेन-देन का जिक्र हुआ है, जो सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाती है। विपक्षी नेता का कहना है कि डीएमके सरकार ने जनता के अधिकार और संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की बजाय केवल सत्ता और राजनीतिक लाभ के लिए अपनी कार्यप्रणाली का दुरुपयोग किया है।

राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पलानीस्वामी ने आग्रह किया कि इन आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग के माध्यम से कराई जाए। उनका कहना है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है कि जनता के सामने सचाई आए और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की गंभीरता उजागर हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि इन व्यापक वित्तीय घोटालों की जांच नहीं की गई, तो राज्य की शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पलानीस्वामी की यह कार्रवाई न केवल डीएमके सरकार को सीधे निशाने पर लेती है बल्कि आगामी चुनावी रणनीतियों और राज्य में विपक्ष की सक्रियता का भी संकेत देती है। विपक्ष का दावा है कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति, भारी कर्ज और कथित भ्रष्टाचार ने आम जनता के जीवन और विकास परियोजनाओं को प्रभावित किया है। इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में विरोध और सत्ता के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर दिया है। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राज्यपाल और उच्च न्यायिक निकाय इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कराते हैं, तो वह राज्य में व्यापक जन आंदोलनों और आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। राजनीतिक मंच पर यह मामला नए बहस और विवाद को जन्म दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया से केवल वर्तमान सरकार की साख ही नहीं, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र और वित्तीय पारदर्शिता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु में जनता और मीडिया इस मामले पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, और आगामी समय में राजनीतिक और न्यायिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव अगले चुनावों और राज्य के शासन पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।

प्रियांक खरगे का आरएसएस पर हमला: विकास की राह में बाधा और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल

(जीएनएस)। बंगलूरू। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को देश की राजनीति में एक बार फिर सुर्खियां बटोरते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। यह टिप्पणी उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले को लेकर सामने आई, जिसमें उन्होंने संगठन की पारदर्शिता और वित्तीय संरचना पर सवाल उठाए थे। मामले की सुनवाई में एक विशेष अदालत ने खरगे और उनके राज्य के साथी मंत्री दिनेश गुंडू राव को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार का लेख साझा करते हुए प्रियांक खरगे ने लिखा कि यह मामला आरएसएस के स्वयंसेवकों की ओर से दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनके द्वारा उठाए गए सवालों का प्रतिशोध है। उनके पोस्ट में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें भगवत ने कहा था कि संगठन अपने स्वयंसेवकों के चंदे से चलता है। खरगे ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए और संगठन से स्पष्टीकरण मांगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा लोगों का समूह अपने "कठपुतलियों" का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ मामले दर्ज करवा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आरएसएस पर जायज सवाल उठा रहे हैं। खरगे ने स्पष्ट किया, "आरएसएस राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।" उन्होंने मोहन भागवत के दावे का हवाला देते हुए पूछा कि ये स्वयंसेवक कौन हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। खरगे ने दान की पारदर्शिता, स्वरूप और उसके प्राप्ति के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए। उनके अनुसार, यदि आरएसएस पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम करता है, तो दान सीधे संगठन को उसकी पंजीकृत संस्था के तहत क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने संगठन की वित्तीय और संगठनात्मक संरचना, पूर्णकालिक प्रचारकों को वेतन देने का स्रोत और बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों, अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों का वित्तपोषण कैसे होता है, इस पर भी सवाल उठाया।

प्रियांक खरगे की यह टिप्पणी राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर चर्चा का केंद्र बन गई है। कर्नाटक में उनके खिलाफ मानहानि मामले की कानूनी प्रक्रिया अब अदालत में चल रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि केवल आरएसएस के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक विकास की दिशा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य है।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रियांक खरगे की इस टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को फिर से गरम कर दिया है। उनका तर्क है कि जब तक किसी संगठन की वित्तीय और संगठनात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक लोकतांत्रिक विकास और नीतिगत सुधारों में बाधा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विरोध का नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है।

कर्नाटक की राजनीतिक पृष्ठभूमि में यह विवाद काफी अहम माना जा रहा है। राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल प्रियांक खरगे की यह पहल सीधे राष्ट्रीय संगठन के कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। उनका कहना है कि किसी भी संगठन के वित्तीय और संगठनात्मक मामलों में पारदर्शिता लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि यह सुनिश्चित नहीं की गई तो देश के व्यापक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

इस घटनाक्रम ने मीडिया और आम जनता में आरएसएस की भूमिका, उसके दान और प्रचारकों की वित्तीय व्यवस्था पर बहस को भी तेज कर दिया है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत और राजनीतिक समीकरण किस दिशा में मुड़ते हैं।

छात्र राजनीति पर अदालत की सख्त नजर, हस्तक्षेप से इनकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों को लेकर दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि छात्रसंघ चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू कराया जाए, ताकि कैंपस राजनीति में धनबल और बाहुबल पर रोक लग सके और शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित रखा जा सके। शीर्ष अदालत ने इस मांग को सुनवाई योग्य मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अपनी सीमाएं हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। अदालत ने प्रारंभिक स्तर पर ही यह स्पष्ट कर दिया कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ का रुख काफी सख्त रहा और मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका न्याय से अधिक प्रचार का माध्यम प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि देश के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, जिससे कैंपस में अनुशासनहीनता, हिंसा और अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। वकील ने तर्क दिया कि निष्पक्ष और स्वस्थ छात्र राजनीति के लिए इन सिफारिशों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है और अदालत को इस दिशा में निर्देश देने चाहिए। हालांकि, पीठ इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की याचिकाएं अकसर केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की जाती हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य न्यायिक समाधान से अधिक सार्वजनिक प्रचार हासिल करना प्रतीत होता है। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

लिंगदोह समिति की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह रिपोर्ट छात्र राजनीति में सुधार की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जाती रही है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने इस समिति का गठन किया था। समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और शैक्षणिक मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव दे। इसका मुख्य उद्देश्य कैंपस राजनीति से धनबल, बाहुबल और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करना था।

लिंगदोह समिति ने अपनी रिपोर्ट में छात्रसंघ चुनावों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। इनमें चुनाव लड़ने वाले छात्रों की आयु सीमा तय करना, चुनाव प्रचार पर खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और शैक्षणिक प्रदर्शन को चुनाव लड़ने की पात्रता से जोड़ना शामिल था। समिति ने स्नातक छात्रों के लिए 17 से 22 वर्ष और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 24 से 25 वर्ष की आयु सीमा तय करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा, प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर और जुलूसों पर भी नियंत्रण की बात कही गई थी, ताकि कैंपस का शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लिंगदोह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद ये सिफारिशें देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई थीं। कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें अपने-अपने स्तर पर लागू भी किया, हालांकि व्यावहारिक स्तर पर इनके पालन को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं।

अफवाहों के झोंकों में सच्चाई की मजबूती वाराणसी रोपवे पर भरोसे की परीक्षा

(जीएनएस)। वाराणसी। काशी अपनी परंपरा, आस्था और निरंतर बदलती आधुनिकता के संगम के लिए जानी जाती है। इसी क्रम में शहर को यातायात की नई सौगात देने वाली देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। यह परियोजना जहां एक ओर संकरी गलियों, बढ़ते यातायात दबाव और प्रदूषण की समस्या का आधुनिक समाधान मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इसे लेकर अनावश्यक आशंकाओं को जन्म दे दिया है। तेज हवा में हिलते एक खाली गंडोला के दृश्य ने कुछ ही घंटों में ऐसा माहौल बना दिया, मानो परियोजना की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया हो। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग और कहीं अधिक संतुलित है। निर्माणाधीन वाराणसी रोपवे परियोजना अपने अंतिम चरण में है। परियोजना का निर्माण कर रही नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड इस समय रोपवे के ट्रायल रन और तकनीकी परीक्षण कर रही है। यही वह चरण होता है, जिसमें किसी भी परिवहन प्रणाली को आम जनता के लिए खोलने से पहले हर संभावित परिस्थिति में परखा जाता है। तेज हवा, अचानक भार परिवर्तन, आपातकालीन स्थिति, ब्रेकिंग सिस्टम और संचार तंत्र—इन सभी पहलुओं की जांच इसी दौरान की जाती है। ट्रायल का उद्देश्य ही यही होता है कि वास्तविक संचालन से पहले हर कमजोरी को पहचाना और दूर किया जा सके। इसी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में तेज हवा के बीच रोपवे का एक खाली गंडोला कुछ हद तक हिलता हुआ दिखाई देता है। नीचे सड़क से गुजर रहा एक बाइक सवार रुककर ऊपर देखने लगता है और यही दृश्य लोगों के मन में डर पैदा करने का माध्यम बन गया। देखते ही देखते वीडियो को अलग-अलग दावों के साथ साझा किया जाने लगा। कहीं इसे तकनीकी खराबी बताया गया, तो कहीं यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाला सिस्टम करार दिया गया। सोशल मीडिया के इस दौर में अधूरी जानकारी और भावनात्मक प्रतिक्रिया अक्सर तथ्यों पर भारी पड़ जाती है, और यही इस मामले में भी हुआ। वायरल वीडियो के बाद फैली आशंकाओं पर एनएचएलएमएल ने स्पष्ट और ठोस बयान जारी किया। कंपनी ने साफ कहा कि यह वीडियो भ्रामक है और इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। जिस गंडोला का वीडियो वायरल हुआ, वह पूरी तरह खाली था और यह घटना रोपवे के नियमित ट्रायल का हिस्सा थी। कंपनी के अनुसार, इस दृश्य का रोपवे की सुरक्षा, मजबूती या तकनीकी विश्वसनीयता से कोई नकारात्मक संबंध नहीं है। बल्कि, यह तो उस परीक्षण प्रक्रिया का प्रमाण है, जिसमें सिस्टम को वास्तविक और कठिन परिस्थितियों में परखा जा रहा है। एनएचएलएमएल का कहना है कि वाराणसी रोपवे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें विशेष रूप से यूरोपीय सुरक्षा कोड्स का पालन किया गया है। दुनिया के कई देशों में शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे परिवहन एक सामान्य और सुरक्षित व्यवस्था मानी जाती है। वहां तेज हवा के दौरान गंडोला का नियंत्रित रूप से हिलना असामान्य नहीं होता, बल्कि यह सिस्टम की लचीलापन क्षमता और संतुलन का हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि गंडोला हिला या नहीं, बल्कि यह है कि सिस्टम ने उस स्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया दी और क्या सभी सुरक्षा मानक सक्रिय रहे। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, परीक्षणों के दौरान हवा की गति मापने वाले सेंसर, केबल की तनाव क्षमता, गंडोला की स्थिरता और आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम को अलग-अलग स्तरों पर जांचा जाता है। यदि हवा की गति तय मानकों से अधिक होती है, तो सिस्टम स्वतः अलर्ट मोड में चला जाता है और आवश्यकता पड़ने पर संचालन रोक दिया जाता है।

संपादकीय

नए साल से ज्यादा पुराना हम

नया साल आते ही लगता है जैसे समय ने हमें एक नया बस्ता थमा दिया हो, जिसमें हमने बिना देखे-सोचे अपनी सारी उम्मीदें, अधूरी इच्छाएं, टूटे संकल्प और अधपके सपने भर दिए हों। घड़ी की सुई जैसे ही बारह को छूती है, हम अचानक अपने पुराने जीवन से नाराज़ हो जाते हैं। जो आदतें कल तक हमारे साथ सांस लेती थीं, वही आदतें आज हमें चुभने लगती हैं। हम खुद से वादा करते हैं कि कल से जिम जाएंगे, कल से सिगरेट छोड़ देंगे, कल से खाने-पीने में अनुशासन आ जाएगा और कल से जिंदगी एक सीधी, साफ और सफल रेखा पर चलने लगेगी। नया साल हमारे लिए एक तारीख नहीं, बल्कि एक बहाना बन जाता है, जिसमें हम अपनी सारी कमज़ोरियों को टाल देते हैं।

हर नया साल एक झूठी तसल्ली लेकर आता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। जैसे बीती रात के साथ ही हमारी नाकामियां भी सो गई हों और सुबह उठते ही हम एक नए इंसान में बदल जाएंगे। यह सोच अपने आप में बहुत मासूम है और शायद इसी मासूमियत के कारण हर साल दोहराई जाती है। हम मान लेते हैं कि समय कोई जादू की छड़ी है, जो एक बार घूमी और जीवन की सारी उलझनें सुलझ गईं। जबकि सच यह है कि समय कुछ नहीं करता, वह सिर्फ चलता है। चलना उसका धर्म है, बदलना हमारा काम है, और इसी काम से हम सबसे ज्यादा बचते हैं।

दुनिया भी नए साल से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल लेती है। जैसे रातों-रात सीमाएं शांत हो जाएंगी, युद्ध थम जाएंगे और राजनीति में शालीनता आ जाएगी। पाकिस्तान जैसा दुष्ट देश एक रात में सुधर जाएगा, यह उम्मीद उतनी ही भोली है जितनी यह उम्मीद कि इंसान बिना मेहनत के सफल हो जाएगा। अमेरिका में बैठा ट्रंप सत्ता और लालच का चोला उतारकर सुबह-सुबह किसी साधु की तरह उठ जाएगा, यह कल्पना भी नए साल के नशे में ही संभव है। सत्ता की भूख, देशों की दुश्मनी और बाजार का लालच तारीख देखकर नहीं बदलते। ये सब भी इंसानी आदतों की तरह जिद्दी होते हैं। नया साल आते ही सोशल मीडिया उम्मीदों का मेला बन जाता है। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, मोटिवेशनल लाइनें और नए लक्ष्य तैरते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो सब लोग अचानक बहुत समझदार और अनुशासित हो गए हों। लेकिन इस चमक के पीछे एक अजीब-सा डर छुपा होता है। डर इस बात का कि अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। इसलिए हम अपने नए साल को इतना भारी बना देते हैं कि वह आते ही हांफने लगता है। उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि साल को खुद संभलने का मौका ही नहीं मिलता। संकल्प लेना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह मेहनत का भ्रम पैदा करता है। हमें लगता है कि हमने कुछ कर लिया, जबकि हमने सिर्फ कहा होता है। असली मेहनत तो अगले दिन सुबह शुरू होती है, जब अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। जिम की फीस भर देना आसान है, वहां रोज़ जाना मुश्किल। सिगरेट छोड़ने का ऐलान करना आसान है, तनाव के समय खुद को रोकना मुश्किल। अनुशासन की बातें करना आसान है, भूख और स्वाद के बीच संतुलन बनाना मुश्किल। यही वजह है कि हमारे ज्यादातर संकल्प कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ देते हैं। नया साल दरअसल कोई चमत्कार नहीं करता। वह हमें वही लौटाकर देता है जो हम रोज़ करते हैं। अगर हमारी आदतें वही हैं, तो परिणाम भी वही होंगे। लेकिन हम परिणामों के लिए साल को दोष देते हैं। कहते हैं यह साल ही खराब है, इसमें कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। शायद साल खराब नहीं होता, हम अपने बोझ से उसे खराब कर देते हैं। हम उससे उम्मीद करते हैं कि वह हमें बदले, जबकि उसे तो बस गुजर जाना है। अगर नए साल के संकल्पों से बिजली बन सकती, तो यह देश कब का रोशन हो चुका होता। हर साल करोड़ों लोग करोड़ों वादे करते हैं और उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि उससे बड़े-बड़े कारखाने चल सकते हैं। अगर इन संकल्पों से पहाड़ बनाए जा सकते, तो इतना विशाल पहाड़ खड़ा होता कि एवरेस्ट भी सिर झुकाकर कहता, बड़े मियां नमस्कार। लेकिन यह सारी ऊर्जा हवा में घुल जाती है, क्योंकि संकल्प जमीन पर नहीं उतरते। वे कागज और पोस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं।

असल बदलाव न तो शोर करता है और न तारीख देखता है। वह धीरे-धीरे आता है, बिना किसी घोषणा के। वह उस दिन आता है जब हम बिना बताए एक सिगरेट कम पीते हैं, एक बहाना कम बनाते हैं या एक कदम ज्यादा चलते हैं। बदलाव कोई उत्सव नहीं, वह एक आदत है। उसे न नए साल की जरूरत होती है और न तालियों की। वह रोज़ के छोटे फैसलों में छुपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

शायद नए साल से हमें इतना ही सीखना चाहिए कि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीदों का बोझ डालना गलत है। साल कोई मजदूर नहीं, जिसे हम अपने सपनों का बोझ उठाने को कह दें। अगर हम खुद थोड़ा जिम्मेदार हो जाएं, तो हर दिन नया साल बन सकता है। तब नए साल का बस्ता हल्का होगा और सफर थोड़ा आसान। वरना हर साल वही कहानी दोहराई जाएगी और नया साल उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ, चुपचाप गुजर जाएगा।

महिला कैदियों हेतु लिंग-संवेदनशील सज़ा नीति बने

> “ महिला कैदियों पर अपनी रिपोर्ट (1987) में, बन्दिनियों की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने कहा था कि सामाजिक मूल्य जड़वत हो गए हैं और सत्ता के अंग अहंकारी रूप से पुरुषोचित हैं, महिलाओं के लिए एक अलग 'भावपूर्ण दण्डशास्त्र' और 'सुधारात्मक दृष्टिकोण' अपनाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'कारागार बंदियों के मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। एक सत्र में महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील जेल सुधार पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप उनके सार्थक पुनर्वास को सुनिश्चित करने वाली 'महिलाओं के लिए हिरासत में न्याय' पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2023 तक देश की विभिन्न जेलों में 21,510 महिला कैदी और 1492 शिशु बन्द थे। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी माताओं के साथ जेल में रहने की अनुमति है, यदि उनकी देखभाल के लिए बाहर कोई उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध न हो। शिशुओं के साथ उनकी 1318 माताओं में से 1049 विचाराधीन कैदी थी और श्ोष 249 महिलाएं दोष-सिद्ध महिलाएं थीं। देश की जेलों में महिला कैदियों की संख्या 4 प्रतिशत है। उनकी कैद मानवाधिकारों से जुड़ी अनेक चिन्ताएं उत्पन्न करती है, विशेषतया उनके बच्चों के सम्बन्ध में। महिला अपराधियों का कारावास न्याय-शास्त्र की दुविधा की ओर भी इशारा करता है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान ही दण्ड प्रक्रिया और सुधारात्मक मानकों के अधीन रखा जाए।

महिलाओं का अपराध क्षणिक आवेश की परिणति होता है। महिला सौंदर्य, रचनात्मकता, देखभाल और प्रेम, इच्छा, समृद्धि और सृजन की प्रतिमूर्ति होती है और अपराध-प्रवृत्ति उसके स्वभाव में नहीं है। महिलाओं द्वारा अपराध करने के पीछे के कारणों और उद्देश्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे ऐसा मुख्य रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करती हैं, जब उनके पास अपने बच्चों और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचता है। कभी-कभी, महिलाएं लैंगिक रूप से असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था और नारीत्व को ठेस पहुंचाने वाले मानदण्डों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए भी कानून तोड़ने पर मजबूर होती हैं। अक्सर, महिला अपराधी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कथित पारिवारिक सम्मान की रक्षा और विरोधियों से बदला लेने के लिए अपराधों में संलिप्त हो जाया करती हैं। लगभग हर स्थिति में, महिला अपराधी परिस्थितियों की शिकार होती हैं। उन्हें अपने दोषपूर्ण पालन-पोषण और प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण की कीमत चुकानी पड़ती है।

80 प्रतिशत से अधिक महिला जेल बन्दिनियां विचाराधीन कैदी हैं। यह विडंबना है कि महिला अपराधियों के साथ पुरुष अपराधियों के समान ही व्यवहार किया जाता है। यह जोगिन्दर कुमार (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के विपरीत है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि गिरफ्तारियां जरूरत के आधार पर होनी चाहिए। गिरफ्तारियां तभी न्याय-संगत होती हैं जब उन्हें आगे होने वाले अपराधों को रोकने, या अपराध के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया हो कि अपराधी अदालती कार्यवाही से नहीं भागेगा। महिला अपराधियों की गिरफ्तारी इस दृष्टि से तार्किक नहीं है क्योंकि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति आमतौर पर क्षणिक होती है और आमतौर पर बदले की भावना से प्रेरित नहीं होती।

इस प्रकार, विचाराधीन महिलाओं की हिरासत न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा श्ाक्ति का एक उद्देश्यहीन प्रदर्शन ही प्रतीत होती है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखना अनावश्यक है। कोई कारण नहीं है कि महिलाओं को अदालतों द्वारा जमानत पर रिहा न किया जा सके, भले ही उन्हें पुलिस द्वारा बिना सोचे-समझे गिरफ्तार कर लिया गया हो।

लिंग-संवेदनशील सजा-नीति के अभाव में, महिला दोषियों को भी पुरुषों के समान ही दण्डात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है। निःसंदेह, महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से भिन्न होती हैं। सामुदायिक सेवा, सजा से पहले और बाद में परिवीक्षा पर रिहाई, अनिवार्य परामर्श और जुर्माना आदि जैसे गैर-हिरासती सुधार विकल्पों की हकदार हैं। सामाजिकता पर आधारित सुधार-उपाय महिला अपराधिकता के निराकरण के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं।

महिलाओं को असाधारण मामलों में ही कैद किया जाना चाहिए, वह भी उनके घरों के पास की जेलों में। प्रत्येक जिला जेल में महिला अपराधियों को रखने के लिए अलग महिला बैरकों की आवश्यकता है। इन बैरकों की वास्तुकला में स्त्री-उन्मुखता और घर जैसे वातावरण की परिकल्पना होनी चाहिए।

महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के 77 प्रतिशत पीड़ित उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति होते हैं, परिणामस्वरूप, महिला कैदियों को आमतौर पर उनके प्रियजनों द्वारा त्याग दिया जाता है। अकेलापन उन्हें मानसिक अवसाद में धकेल देता है। निःसंदेह, जेल में बन्द महिलाओं का जीवन कष्ट-प्रद है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक भीड़भाड़ वाली बैरकों में बन्द रखा जाता है। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैंटीन की बहुत सीमित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 'सैनिटरी नैपकिन' और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था असन्तोषजनक है। उन्हें काम के अवसर श्ाायद ही उपलब्ध हों और अकेलापन उनकी नियति बन जाता है।

जेल में बन्द अधिकांश महिलाओं के पास धन का अभाव होता है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। लगभग हर महिला कैदी जेल में आते ही अपनी पहचान खोने का दंश झेलती है, वे 'अन्दर भय और बाहर भक्ति' के साथ जेलों में जीवनयापन करती हैं। प्रतिशोध और सजा का डर उन्हें बहरा और गूंगा बना देता है। महिला कैदी आमतौर पर भावनात्मक रूप से परेशान और बौद्धिक रूप से भ्रमित हो जाती हैं। फलतः श्ाोषण का शिकार होने की स्थिति में आ जाती हैं।

पर्याप्त बाल देखभाल सुविधाओं के अभाव में महिला कैदियों के बच्चों को भी उनकी माताओं के साथ प्रतिदिन 16-18 घंटे तक बन्द रखा जाता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के रूप में उनका आदर्श निवास सरकारी बाल-गृह होने चाहिए। महिला कैदियों की समस्याएं कानून की ख़ामियों और बुनियादी ढांचे की कमियों, दोनों का परिणाम हैं। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की माताओं के लिए अनिवार्य जमानत या सज़ा के निलम्बन का प्रावधान करने के लिए कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। महिलाओं और उनके बच्चों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण योजनाओं के तहत अलग लाभार्थी समूहों के रूप में वगीकृत किया जाना चाहिए।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली अधिकांशतया पुरुष-केन्द्रित है, यह पुरुषों की, पुरुषों द्वारा, पुरुषों के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। महिला कैदियों पर अपनी रिपोर्ट (1987) में, बन्दिनियों की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने कहा था कि सामाजिक मूल्य जड़वत हो गए हैं और सत्ता के अंग अहंकारी रूप से पुरुषोचित हैं, महिलाओं के लिए एक अलग 'भावपूर्ण दण्डशास्त्र' और 'सुधारात्मक दृष्टिकोण' अपनाने की जरूरत है। पुरुष और महिलाएं श्ाारीरिक और भावनात्मक रूप से एक ही समूह की अलग-अलग प्रजातियां हैं, इसलिए उनके लिए अलग-अलग 'हिरासती न्याय' और पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता है।

प्रेरणा

अपमान के सामने भी करुणा की विजय

काशी की गलियों में उस दिन भी वही चहल-पहल थी, वही शोर, वही जीवन की गति। संत रैदास अपने अनुयायियों के बीच बैठे हुए थे और सहज भाषा में जीवन का सार समझा रहे थे। उनके शब्दों में न कोई आडंबर था, न कोई ऊँच-नीच का भेद। वे मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की बात करते थे। लेकिन हर समय, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांति और विवेक चुभता है। उसी भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए। उन्होंने पहले व्यंग्य किए, फिर छींटाकशी की और बात इतनी बढ़ गई कि वे शारीरिक हिंसा पर उतारू हो गए।

यह दृश्य देखकर रैदास के अनुयायियों का खून खौल उठा। जिन हाथों में अभी तक शांति थी, उनमें क्रोध भरने लगा। भक्तों को लगा कि यदि वे चुप रहे तो यह अन्याय होगा। वे आगे बढ़े, उनके चेहरों पर गुस्सा था और आंखों में प्रतिशोध की चमक। उसी क्षण संत रैदास ने एक वाक्य कहा, जिसने सबको ठिठका दिया। उन्होंने कहा, 'मारो-मारो, पर इन्हें नहीं।' यह वाक्य सुनकर सब रुक गए। यह कैसी बात थी? मारो भी और इन्हें नहीं भी। भक्त एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो किसी पहेली में उलझ गए हों। भक्तों ने विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब रैदास ने बहुत शांत स्वर में कहा कि यदि मारना ही है तो अपने गुस्से को मारो, अपने अहंकार को मारो। उस व्यवस्था को मारो जो इंसान को इंसान से लड़ना सिखाती है। ये लोग नादान हैं, अपने अहंकार और अज्ञान के वशीभूत हैं। अगर तुम भी वही करोगे जो ये कर रहे हैं, तो तुममें और इनमें क्या अंतर रह जाएगा। उस समय रैदास के शब्द केवल समझाइश नहीं थे, वे एक आईना थे, जिसमें हर भक्त अपना चेहरा देख रहा था।

यह घटना केवल एक संत की सहनशीलता की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे क्रोध और विवेक के संघर्ष की कहानी है। क्रोध सबसे आसान रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि अभी बदला लो, अभी चोट का जवाब चोट से दो। लेकिन विवेक हमेशा कठिन रास्ता सुझाता है। वह कहता है कि रुक जाओ, सोचो, और अपने भीतर झांको। रैदास ने उसी कठिन रास्ते को चुना। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकलता। हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है।

उस दिन रैदास ने जो कहा, वह केवल उस क्षण के लिए नहीं था। वह हर समय के लिए था। समाज में जब भी अपमान, अन्याय या हिंसा होती है, सबसे पहले हमारा क्रोध जागता है। हम सोचते हैं कि सामने वाले को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि सबक सिखाने की यह चाह हमें भी उसी स्तर पर ले जाती है, जिस स्तर पर सामने वाला खड़ा है। रैदास यही समझाना चाहते थे कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। आत्मसम्मान शांत रहता है, अहंकार शोर मचाता है।

रैदास की विनम्रता का प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। उनके भक्त शांत हो गए और अपनी जगह बैठ गए। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, बल्कि एक तरह की लज्जा थी। उन्होंने महसूस किया कि वे भी पल भर के लिए उसी रास्ते पर चल पड़े थे, जिस पर वे दूसरों को दोष दे रहे थे। यह परिवर्तन देख उपद्रवी भी ठिठक गए। उन्हें शायद पहली बार अहसास हुआ कि उनका व्यवहार कितना खोखला है। बिना किसी मारपीट, बिना किसी अपमान के वे चुपचाप वहां से चले गए।

यह प्रसंग हमें सिखाता है कि असली शक्ति हाथ उठाने में नहीं, हाथ रोक लेने में होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर के दुश्मन से लड़ना सबसे कठिन। गुस्सा, अहंकार और घृणा ये वही दुश्मन हैं, जो हमें भीतर से कमजोर करते हैं। रैदास ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चा सुधार पहले भीतर से शुरू होता है।

आज के समय में यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। चारों ओर असहिष्णुता बढ़ रही है। छोटी-छोटी बातों पर लोग हिंसा पर उतर आते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देता है। हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे समय में रैदास का संदेश हमें याद दिलाता है कि यदि हम भी गुस्से के वश में आ गए, तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे हमें शिकायत है।

रैदास की शिक्षा किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वह मनुष्य मात्र के लिए है। उन्होंने बताया कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब हम अपने भीतर के क्रोध को जीत लेते हैं, तभी हम समाज में शांति ला सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और धैर्य केवल नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि सबसे प्रभावी हथियार भी हैं।

इस घटना के बाद रैदास के अनुयायियों ने केवल एक पाठ नहीं सीखा, बल्कि एक जीवन दृष्टि पाई। उन्होंने समझा कि गुरु का सम्मान केवल उनकी रक्षा करने में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को जीने में है। रैदास ने उस दिन यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा मर्दन बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि अपने गुस्से और अहंकार का होता है। यही वह विजय है, जो मनुष्य को ऊँचा उठाती है और समाज को बेहतर बनाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर सवाल

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करके हथकड़ियों में उनके देश से उठाकर न्यूयॉर्क में लाने की घटना को लेकर भारत की संतुलित प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना राष्ट्रीय कूटनीतिक लिहाज से सही नहीं कही जाएगी। वैसे भी ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष के दौर में तो कड़ी प्रतिक्रिया अपने राष्ट्रीय हितों को संकट में डालने जैसा ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरह भारत के लोगों ने इस कार्रवाई के विरोध में प्रतिक्रिया जताई है, उसे भी भारतीय लोक की स्वाभाविक प्रक्रिया का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। भारतीय लोक स्वभाव से ही लोकतांत्रिक है और उसे लोकतांत्रिक सत्ताओं का सैनिक कार्रवाई के जरिए उखाड़ना पसंद नहीं रहा है। भारतीय लोक का मानस कमजोर के पक्ष में खड़े होने का रहा है। इसलिए अधिसंख्य भारतीय प्रतिक्रियाएं निकोलस मादुरो के पक्ष और अमेरिका के विरोध में हैं। अमेरिकी कार्रवाई ने दो तरह प्रस्थापनाएं की हैं। पहली यह कि ताकतवर के लिए कुछ भी करना संभव है। वह उसे नियमों और कानूनों की परिभाषा में बांध सकता है। दुनिया लाख चिल्लाती रहे कि किसी राष्ट्राध्यक्ष की सत्ता को उखाड़ फेंकना और उसे गिरफ्तार करके अपने कानूनों के दायरे में लाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन इसका अमेरिका की सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अमेरिका ने एक तरह से इतिहास को ही दोहराया है। अमेरिका अपने हितों के खिलाफ जिस देश को सिर उठाते देखता है, उसके खिलाफ उसे सैनिक, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। इस मौके पर जार्ज बुश सीनियर के दौर को याद किया जाना चाहिए। कुवैत में इराकी सेना की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने खाड़ी युद्ध छेड़ दिया था। बेशक इस युद्ध की आग में झुलसने के चलते वे सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाए। लेकिन उनके अधूरे कार्य को उनके बेटे जार्ज बुश जूनियर ने पूरा किया। बेशक इसके लिए मुस्लिम चरमपंथियों और ओसामा बिन लादेन के कुख्यात संगठन अलकायदा ने मौका मुहैया कराया। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सत्ता को तहस-नहस करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश जूनियर और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक बहाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इराक भेजे गए वैज्ञानिकों और पर्यवेक्षकों ने कथित रूप से रिपोर्ट दी कि इराक के पास व्यापक जनसंहार के रासायनिक हथियार हैं। अमेरिका की नजर में सद्दाम तानाशाह थे,इस लिहाज से ये हथियार मानवता के लिए घातक हो सकते थे।फिर क्या था,संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव की आड़ में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराकी शासन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका की अगुआई वाली सेनाओं के हमले में इराक तहस-नहस हो गया। सद्दाम गिरफ्तार कर लिए गए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें व्यापक नरसंहार का दोषी ठहराते हुए फांसी पर लटका दिया गया। बाद के दिनों में बीबीसी ने रिपोर्ट दी कि जिन घातक रासायनिक हथियारों को खत्म करने के नाम पर इराक पर मित्र देशों की सेनाओं ने हमला किया, असलियत में ऐसे हथियार तो इराक के पास थे ही नहीं। बीबीसी को यह खबर लीक करने का शक हथियार जांचने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम के सदस्य रहे ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम केली पर किया गया। बीबीसी के कई अधिकारियों और पत्रकारों को इस खबर के लिए अपनी नौकरी गवांनी पड़ी। एक सुबह टहलने गए विलियम केली भी रास्ते में मृत पाए गए। इराक में अमेरिकी तर्ज का लोकतंत्र स्थापित तो हो गया है,लेकिन क्या वहां शांति आ पाई है? कुछ ऐसा ही यक्ष प्रश्न वेनेजुएला को लेकर उभरने वाला है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में जो सत्ता स्थापित हुई है, क्या वह सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करके वहां नशा के कारोबार को रोक पाएगी। नशे के कारोबार की बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने मादुरो पर बड़ा आरोप लगाया है कि वे नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे अमेरिकी हितों को चोट पहुंच रही थी। हालांकि उनके इस आरोप को अमेरिका की ही उपराष्ट्रपति रहीं कमला हैरिस ने नकारा है। उनका कहना है कि ट्रंप की कार्रवाई की मूल वजह के पीछे तेल का खेल है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अनुमान है कि यह भंडार करीब 303 अरब बैरल है। लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन में वह बहुत पीछे है। वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादकों की जो सूची है, उसमें वेनेजुएला 21वें स्थान पर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्पादन के लिए वेनेजुएला के पास बुनियादी ढांचे की बेहद कमी है। इसके साथ ही मादुरो की सत्ता के चलते यहां लगातार अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। इसकी वजह से वह उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध के पहले तक भारत वेनेजुएला का दूसरे नंबर का तेल आयातक था। भारत की अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संतुलित प्रतिक्रिया की एक बड़ी वजह भारतीय तेल कंपनियों का फंसा यहां पैसा है। कच्चे तेल के उत्पादन के लिए भारतीय तेल कंपनियों ने यहां निवेश कर रखा है। भारत के करीब नौ हजार करोड़ रुपए यहां फंसे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बदली परिस्थितियों में भारत को यह रकम मिल सकती है या फिर तेल का आयात बढ़ सकता है। बहरहाल अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसका मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे ट्रंप की कोशिश अपने परिवार के नियंत्रण वाली तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। अमेरिकी कार्रवाई ने एक सवाल यह भी उठाया है कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ की अब भी जरूरत है। इस कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

अभियान

श्रद्धा, तप और मोक्ष की साधना का संगम: माघ मेले में कल्पवास की अखंड परम्परा

प्रयागराज की धरती पर जब माघ मास की पहली पूर्णिमा का सूर्योदय होता है, तब संगम तट केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं रह जाता, वह आत्मा की प्रयोगशाला बन जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर 3 जनवरी से प्रारम्भ हुआ माघ मेला भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जिसमें कठिन संयम, साधना और त्याग को जीवन की सर्वोच्च साधना माना गया है। दूर-दराज़ से आए साधु-संत, धर्माचार्य और सामान्य गृहस्थ श्रद्धालु रेत पर बने तंबुओं और घास-फूस की झोपड़ियों में एक महीने के लिए अपना संसार बसाकर उस जीवन से दूरी बना लेते हैं, जिसमें सुविधा, भोग और जल्दबाज़ी प्रधान होती है।

संगम तट पर बसने वाला यह अस्थायी संसार भीतर से अत्यंत स्थायी प्रभाव छोड़ता है। कल्पवास माघ मेले की आत्मा है और इसे गृहस्थ जीवन की सबसे कठिन साधना कहा जाता है। कल्पवास केवल किसी स्थान पर निवास करने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को नियमों, मर्यादाओं और संयम में बांधने का संकल्प है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलने वाली यह साधना लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुखों के निवारण का माध्यम मानी जाती है। शास्त्रों में इसे मोक्ष की दिशा में उठाया गया एक दृढ़ कदम कहा गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण करना सीखता है। कल्पवास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पुराणों, उपनिषदों और रामायण जैसे ग्रंथों में इसके उल्लेख मिलते हैं। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार जन्म-जन्मांतर के पापों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए संगम तट पर कल्पवास का विधान किया गया। इस साधना का प्रारम्भ बाह्य शुद्धि से होता है। पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु क्षौर कर्म अर्थात मुंडन कराते हैं, जिसे अहंकार और पुराने संस्कारों के त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात संगम स्नान कर कल्पवासी संकल्प लेते हैं। यह संकल्प केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि स्वयं के साथ किया गया एक कठोर अनुबंध होता है।

संकल्प की विधि में कल्पवासी अपना नाम, गोत्र और साधना का उद्देश्य बताता है। परंपरागत रूप से मोक्ष प्राप्ति और कष्ट निवारण ही इसका मुख्य लक्ष्य रहा है, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में अब लोग पारिवारिक समस्याओं के समाधान, संतान प्राप्ति, वंश परंपरा की निरंतरता, व्यापार और रोजगार की उन्नति जैसी कामनाओं के साथ भी कल्पवास करते हैं। उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन साधना की कठिनता सभी के लिए समान रहती है। संकल्प के बाद कल्पवासी अपने शिविर में शालिग्राम या इष्ट देवता की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना कर पूजा करते हैं और शिविर के बाहर जौ की बुवाई तथा तुलसी का पौधा रोपते हैं। यह कर्म सृजन, जीवन और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है।

कल्पवास को गृहस्थ जीवन की कठोर साधना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आराम और सुविधा का स्थान नहीं होता। दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से प्रारम्भ होती है। माघ मास की तीखी ठंड में दिन में तीन बार गंगा स्नान का विधान है। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर इष्ट देव की पूजा की जाती है। इसके पश्चात अन्नदान का विधान है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन गंगापुत्र, दरिद्र नारायण और पुरोहित को भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। यह दान केवल पुण्य अर्जन नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की भावना को जीवित रखने का साधन है।

दिन में केवल एक समय सादा सात्विक भोजन किया जाता है, जो सामान्यतः अपराह्न में तैयार होता है। भोजन से पूर्व स्नान का विधान है, हालांकि सभी इसका कठोर पालन नहीं कर पाते। अनेक लोग गंगाजल का आचमन कर लेते हैं। सायंकाल गोधूलि बेला में तीसरा स्नान किया जाता है। वृद्ध और अस्वस्थ कल्पवासी गंगा तट पर जाकर स्पर्श और आचमन के साथ क्षमा याचना कर लेते हैं। संध्या समय गंगा आरती में सम्मिलित होना या स्वयं दीपदान करना अनिवार्य साधना का हिस्सा माना जाता है।

कल्पवास के दौरान जप, ध्यान और पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। दिन के शेष समय में कल्पवासी प्रवचन, रामकथा, भागवत कथा और अन्य धार्मिक आयोजनों का श्रवण करते हैं। अनेक श्रद्धालु अपने शिविरों में ही भजन-कीर्तन और कथा वाचन करते हैं। इसका उद्देश्य मन को सांसारिक मोह से हटाकर भक्ति और वैराग्य में स्थिर करना होता है। सायंकाल भोजन का निषेध है, लेकिन आवश्यकता होने पर फलाहार या जलपान की अनुमति दी गई है।

कल्पवास की साधना में निषेधों का विशेष महत्व है। मांसाहार, नशा और तामसी भोजन पूर्णतः वर्जित हैं। माना जाता है कि तामसी आहार मन और इंद्रियों को विचलित करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की निंदा—ईश्वर, शास्त्र, गुरु या किसी व्यक्ति की—घोर अपराध मानी गई है। कहा जाता है कि तामसी भोजन का प्रायश्चित संभव है, लेकिन निंदा का नहीं। संकल्प लेने के बाद बिना अपरिहार्य कारण के मेला क्षेत्र छोड़ना भी निषिद्ध है, क्योंकि यह साधना की निरंतरता को भंग करता है।

कल्पवास की अवधि एक माह की होती है, जो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलती है। इस वर्ष यह साधना 3 जनवरी से प्रारम्भ होकर 1 फरवरी को समाप्त होगी। अनेक श्रद्धालु मकर संक्रांति या अन्य तिथियों से आकर कुछ दिन रहकर भी कल्पवास करते हैं। शास्त्रीय मान्यता भले ही पूर्ण न मानी जाए, लेकिन गंगा तट पर जप, तप और दान का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है।

यह महापर्व जाति, पंथ और संप्रदाय के भेद से परे है। यहां आर्य समाज, सिख, कबीर पंथी सहित विभिन्न समुदायों के लोग समान भाव से साधना करते हैं। सिख समाज द्वारा चलाए जाने वाले अन्नक्षेत्र, वस्त्र और कंबल वितरण सेवा और समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कल्पवास का एक चक्र बारह वर्षों का माना गया है। बारह वर्ष पूर्ण होने पर अनेक श्रद्धालु शैया दान करते हैं और पुनः अगले चक्र का संकल्प लेते हैं। महाकुंभ के बाद आयोजित इस माघ मेले में संगम तट पर फैली यह साधना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उलझे मनुष्य के लिए ठहराव, आत्मनिरीक्षण और संयम का संदेश है। रेत पर बसे ये अस्थायी तंबू हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्थिरता बाहरी सुविधाओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और अनुशासन में निहित है। यही माघ मेला और कल्पवास की सबसे बड़ी देन है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति की चेतना को जीवित रखे हुए है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

शहरी विकास वर्ष 2025 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के जल संसाधनों में 92.97 एमएलडी तथा ट्रांसमिशन सिस्टम्स में 528.35 किलोमीटर की वृद्धि

▸▸ हाल में राज्य के 103 शहरों में दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित, 30 शहरों में विभिन्न योजनाओं के तहत जलापूर्ति के कार्य प्रगति पर

▸▸ एससीएडीए सिस्टम से प्रमुख महानगरों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग होती है

▸▸ गुजरात के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू हो रहा है 'मिशन डेली वॉटर सप्लाई'

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार की राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक जलापूर्ति यानी प्रतिदिन जलापूर्ति तथा सुरक्षित पेयजल तक समान पहुँच सुनिश्चित कर राज्य को टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की मंशा है। इसी उद्देश्य से शहरी विकास वर्ष 2025 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के जल संसाधनों में 92.97 एमएलडी तथा ट्रांसमिशन सिस्टम्स में 528.35 किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त; मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में दैनिक आधार पर जलापूर्ति करने के लिए 'मिशन डेली वॉटर सप्लाई' जैसी पहल लागू की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न वॉटर सप्लाई तथा सेनिटेशन संबंधी परियोजनाएँ शुरू करने एवं पहलों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलपमेंट को वेग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है और इस वर्ष के दौरान राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

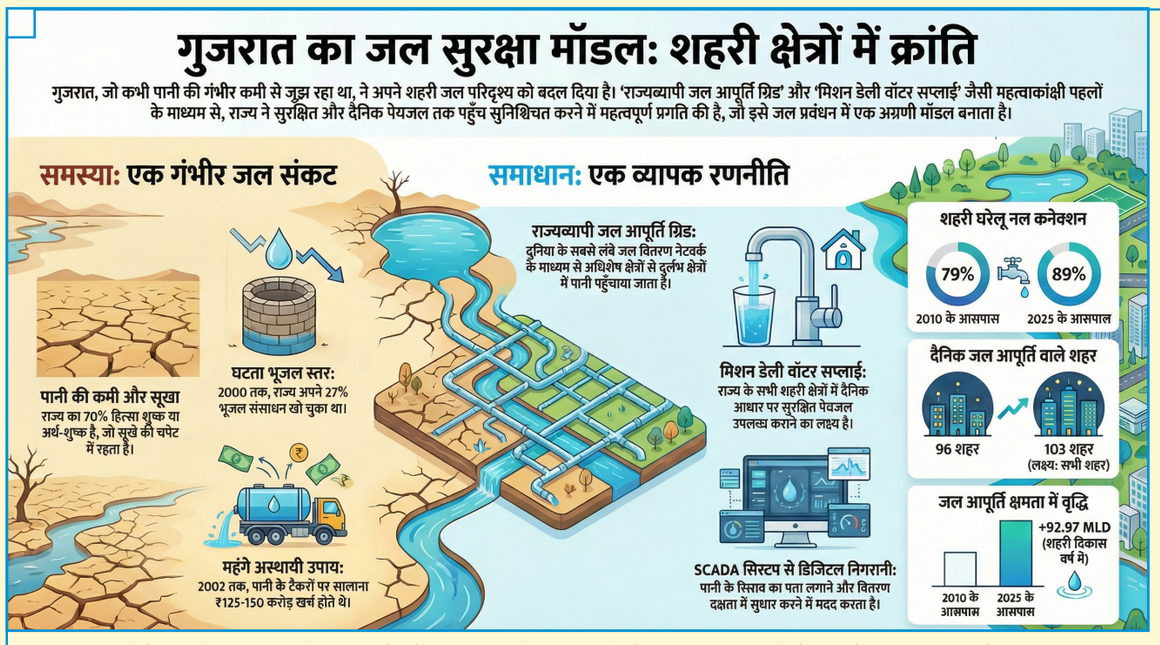

हाल में राज्य के 103 शहरों में प्रतिदिन जलापूर्ति हो रही है

उल्लेखनीय है कि हाल में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा पहलों के अंतर्गत 103 शहरों में दैनिक आधार पर जलापूर्ति की जा रही है। शेष शहरों में से 30 शहरों में विभिन्न योजनाओं के तहत जलापूर्ति के कार्य प्रगति पर हैं। राज्य के शेष 32 स्थानीय निकायों में दैनिक जलापूर्ति हो; इसके लिए मिशन डेली वॉटर सप्लाई लागू किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न घटकों के कार्यों का आयोजन किया गया है।

एससीएडीए सिस्टम से प्रमुख महानगरों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग

शहरी क्षेत्रों में पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन संबंधित सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए प्रमुख महानगरों में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) सिस्टम सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह सिस्टम लीक डिटेक्शन, लो प्रेशर पॉकेट, नॉन-रेवन्यू वॉटर (एनआरडब्लू) में कमी, जरूरी दबाव के साथ प्रतिव्यक्ति जलापूर्ति में सुधार, जरूरी पंपिंग कार्यक्षमता के साथ पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण, वॉल्व मॉनिटरिंग आदि में सहायता करता है। इस सिस्टम के कारण एनआरडब्लू से होने वाले नुकसान में कमी आई है और पानी के समान वितरण तथा अन्य जल संसाधन सेवाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई है। उल्लेखनीय है कि डेली वॉटर सप्लाई मिशन तथा जलापूर्ति संबंधी अन्य योजनाओं एवं पहलों के क्रियान्वयन से आम लोगों को प्रतिदिन पीने योग्य पानी मिलेगा, जिससे दीर्घावधि के लिए जल संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध होने से पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भरता भी घटेगी। शहरों के सुगठित तथा योजनापूर्वक विकास से शहरों में बसने वाले नागरिकों को 'ईज ऑफ लिविंग' का अनुभव प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सहभागी हुए

▸▸ मुख्यमंत्री ने मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण व निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के दिशानिर्देश दिए

▸▸ गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था हो : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल

▸▸ गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा केसों की संख्या में उतरोत्तर कमी होने की जानकारी प्रदान की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में आयोजित उच्च स्तरीय सर्वग्राही समीक्षा बैठक में गांधीनगर शहर में टाइफाइड बीमारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति में महानगर पालिका तथा राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मरीजों के उपचार, रोग नियंत्रण तथा निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों को अधिक सघन बनाने के सुझाव दिए। इस बैठक में गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त ने मुख्यमंत्री को इस बीमारी के नियंत्रण के लिए महानगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में रहकर हो रहे कामकाज का विवरण देते हुए कहा कि अब केसों में उत्तरोत्तर कमी देखने को मिल रही है। महानगर पालिका द्वारा 85 सर्वे टीमें बनाकर 1 लाख 58 हजार से अधिक लोगों का सर्वेलांस किया गया है। क्लोरीन टैबलेट्स और ओआरएस पैकेट का भी पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया है। लीकेज के रिपेयरिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा सभी जल स्रोतों में सुपर क्लोरीनेशन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जलजन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सघन उपाय के रूप में गांधीनगर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रतिदिन सैंपल लेकर उसकी योग्यता और क्लोरीनेशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जल वितरण व्यवस्था करने के स्पष्ट दिशानिर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान में पाइपलाइन से संबंधित जो कार्य प्रगति पर हैं, उनकी फील्ड विजिट करके गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिए। उन्होंने वॉटर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने और लीकेज को तत्काल प्रभाव से रोकने के कदम उठाने की ताकीद की।

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, जल आपूर्ति एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री डॉ. विक्रांत पांडे, शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य कमिश्नर डॉ. रतनकंवर गढवीचारण, गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल की अपील

उत्तरायण मनाए , रेलवे ओवर हेड वायर से दूरी बनाए

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइन के ऊपर 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) हाई वोल्टेज तारें लगी हुई हैं, यह अत्यंत खतरनाक एवं जानलेवा हैं।वडोदरा मंडल आप से अपील करता हे की आप उत्तरायण मनाए एवं अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखे ,रेलवे ट्रैक के पास पतंग न उडाये ।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तरायण/मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर (मांझा) इन हाई वोल्टेज तारों में उलझ जाती है। इस दौरान पतंगों के धागों को निकालने के लिए बांस व बांस पर अन्य धातुके हुक का उपयोग करते हैं । जिसके कारण व्यक्तिओं को बिजली का झटका लगने से जान का खतरा बना रहता हैं ।

इस दौरान २५००० वोल्ट के बिजली के तार टूट कर नीचे गिर सकते हैं, जिससे रेल यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं, व्यवधान के साथ – साथ जान जाने की सम्भावना रहती हैं ।

साथ ही ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारी जब ट्रैक पर कार्य करते हैं, तो इन धागों के संपर्क में आने से गंभीर विद्युत झटके का खतरा बना रहता है।

रेल प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं सतर्क रहें तथा दूसरों को भी अधिक से अधिक जागरूक करें।

अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु कृपया निम्नलिखित सावधानियां अवश्य अपनाएं:

▸▸ रेलवे ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन, पोल एवं ओवरहेड तारों से दूर पतंग उड़ाएं।

▸▸ रेलवे क्षेत्र में गिरी या फंसी हुई पतंग अथवा मांझा उठाने का प्रयास न करें।

▸▸ बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उन्हें रेलवे क्षेत्र से दूर रखें।

सुरक्षित रहें — जिम्मेदारी के साथ उत्तरायण मनाएं।

पश्चिम रेलवे द्वारा RailOne ऐप के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने की पहल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से डिजिटल, त्वरित एवं कैशलेस टिकटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। रेलवन ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट बुकिंग एवं प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी, ग्राहक सहायता आदि जैसी रेलवे की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिकट बुकिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ तथा संबंधित पर्यवेक्षकों को रेलवन ऐप की विशेषताओं के बारे में संवेदनशील किया गया है, ताकि वे यात्रियों को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन एवं प्रेरित कर सकें। वाणिज्यिक पर्यवेक्षक एवं टिकट चेकिंग स्टाफ स्टेशनों पर सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिनके माध्यम से ऐप की उपयोगिता एवं सरलता को उजागर किया जा रहा है। सार्वजनिक जागरूकता को और

अधिक बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर पोस्टर एवं पर्चे प्रदर्शित एवं वितरित किए जा रहे हैं, प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं तथा जन उद्घोषणा (PA) प्रणाली और पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित घोषणाएँ की जा रही हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो 14 जनवरी, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी।

टिकटिंग के अतिरिक्त, रेलवन ऐप पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में ट्रेन सर्च, पीएनआर स्थिति, कोच पोजिशन, ट्रैक योर ट्रेन, ऑर्डर योर फूड, रिफंड दर्ज करना, रेल मदद तथा गो टू वेव्स शामिल हैं।

वर्तमान में यूटीएस (UTS) ऐप का उपयोग कर रहे यात्रियों को भारतीय रेल के ऑल-इन-वन मोबाइल एप्लिकेशन रेलवन पर सहज रूप से स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे एक ही उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग जारी रखने के साथ-साथ अनेक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकें। मौजूदा यूटीएस उपयोगकर्ता प्रदान किए गए इमेज फ्लोचार्ट में दर्शाई गई सरल चरणबद्ध माइग्रेशन प्रक्रिया का पालन करके अपने खातों को रेलवन ऐप में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स का स्थानांतरण संभव हो सकेगा और बिना किसी व्यवधान के सेवाओं का निरंतर उपयोग सुनिश्चित होगा।Flowchart(5).jpeg

रेलवन ऐप तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, एंड्रॉयड तथा iOS दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए QR कोड स्कैनर स्टेशनों पर तथा पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे हैं, जिससे यात्री ऐप तक तुरंत पहुँच प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ 139 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कार्यरत कर्मियों को भी रेलवन ऐप से संबंधित यात्रियों के प्रश्नों का समाधान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। WhatsApp Image 2026-01-06 at 19.04.31.jpeg

श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को R-Wallet के जरिए भुगतान करने पर 3% कैशबैक का लाभ मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से यूटीएस ऐप के वर्तमान उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया कि वे रेलवन ऐप पर स्थानांतरित हों और इसकी एकीकृत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें। साथ ही, अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों (R-Wallet को छोड़कर) पर 3% की छूट अथवा R-Wallet के माध्यम से भुगतान करने पर 3% बोनस के रूप में कैशबैक का लाभ उठाएँ तथा सुरक्षित, सुविधाजनक और कैशलेस डिजिटल टिकटिंग समाधान अपनाकर पश्चिम रेलवे पर सुगम, स्मार्ट और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त करें।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपर्युक्त कार्य के संबंध में कांदिवली में अप फास्ट लाइन पर पॉइंट संख्या 102 के समावेशन हेतु 07/08 जनवरी, 2026 की रात मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक लिया जाएगा। अतिरिक्त रूप से, 08/09.01.2026 को कांदीवली पर पॉइंट्स इनसर्शन और डिसमेंटल के कार्य के लिए अप फास्ट लाइन में 23:15 से 03:15 बजे तक और डाउन फास्ट लाइन में 01:00 से 04:30 बजे तक एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। उपर्युक्त ब्लॉकों तथा पाँचवीं लाइन के निलंबन के साथ गति प्रतिबंध के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

07 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I, II, III में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

गांधीधाम सब डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में पहली बार सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट (TKR) सर्जरी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के सब डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल, गांधीधाम में 05 जनवरी 2026 को पहली बार टोटल नी रिप्लेसमेंट (TKR) सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह जटिल शल्यक्रिया 56 वर्षीय महिला रेलवे लाभार्थी की सब-डिवीजन रेलवे अस्पताल, गांधीधाम के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में की गई। केस-टू-केस आधार पर नियुक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट की विशेषज्ञ टीम द्वारा यह सर्जरी पूर्णतः सुरक्षित, सुचारु एवं सफलतापूर्वक की गई।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि डॉ. रमेश जांगिड, मण्डल चिकित्सा अधिकारी (DMO), गांधीधाम के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है, जो सब-डिवीजन रेलवे अस्पताल, गांधीधाम में उन्नत ऑर्थोपेडिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से भविष्य में रेलवे लाभार्थियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर उन्नयन की दिशा में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

रामनगरिया में आस्था की गर्मी ने ठंड को दी मात, सकट चौथ पर गंगा स्नान और भजन-पूजन का अद्भुत दृश्य

(जीएनएस)। फर्रुखाबाद। रामनगरिया में गंगातट पर स्थित पांचाल घाट पर सकट चौथ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं और संत महात्माओं की आस्था ने ठंडी हवाओं और कड़ाके की शीतलहर को भी बेअसर कर दिया। दिनभर चलने वाले कार्यक्रमों में गंगा स्नान, भजन-पूजन और ध्यान साधना की धूम रही। इस धार्मिक आयोजन में आए कल्पवासियों और साधकों ने अपनी आस्था का परिचय देते हुए कठिन मौसम के बावजूद आयोजन में भाग लिया। रामनगरिया मेले में पंच दशनामी अखाड़े के अध्यक्ष, सत्यगिरी महाराज ने उपस्थित संतों और श्रद्धालुओं को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहर चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, आस्था के आगे कभी बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि साधक और संत किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने भक्ति भाव और ध्यान साधना को नहीं छोड़ते, और यही सच्चा अध्यात्म है। सत्यगिरी महाराज ने गहन आध्यात्मिक व्याख्यान में बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं। कबीर के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "हम न मरे मरीहैय संसारा, हम को मिला जियावन हारा।" उनके अनुसार, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है; यह न जन्म लेती है, न मरती है। इसी प्रकार मन भी नश्वर नहीं है। उन्होंने आगे समझाया कि जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, तब आत्मा तीन दिन तक अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने के लिए व्याकुल रहती है। लेकिन शरीर न मिलने पर आत्मा अपने मूल रूप में लौट आती है और फिर अपने आनंद का अनुभव करती है। सत्यगिरी महाराज ने इसे समझाने के लिए एक जीवंत उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, उसी तरह साधक के अंदर परमात्मा विराजमान होता है। साधक जब ध्यान और चिंतन की मथानी से अपने भीतर के परमात्मा को मथता है, तभी उसे सच्चा आत्मिक आनंद और मानसिक शांति मिलती है। सत्यगिरी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को यह भी बताया कि ध्यान और साधना का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसके माध्यम से साधक "मैं ब्रह्म हूं" की अनुभूति तक पहुंच सकता है। उन्होंने सभी साधकों और श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर बैठे परमात्मा को जानने के लिए नियमित साधना और चिंतन करें, और इसी से आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति संभव है। इस अवसर पर गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश किया। भक्तों ने ठंडे पानी में स्नान करते हुए और भजन गाते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट की। मेला क्षेत्र में उपस्थित संत महात्माओं ने भी गहन ध्यान साधना और भजन-पूजन कर आस्था का वातावरण बनाया। रामनगरिया मेला अपनी परंपरा और धार्मिक महत्व के लिए विख्यात है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स

सी-डॉट C-DOT

विज्ञापन संख्या C-DOTD/HR/REC/2026/01/01
दिनांक: 07 जनवरी 2026

रिक्ति सूचना

सी-डॉट में निम्नलिखित पद की रिक्तियों के लिए सूचना

सी-डीओटी में नीचे उल्लिखित पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र.सं.	पद का नाम	तरीका	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर	रिक्तियों की संख्या	
1.	उप महाप्रबंधक - रणनीतिक योजना एवं समन्वय, रक्षा परियोजना कार्यान्वयन	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	लेवल 13	01	इच्छुक और पात्र उम्मीदवार केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
2.	वैज्ञानिक-बी/सी/डी	सीधी भर्ती पर	लेवल 10/11/12	10	इच्छुक और पात्र उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

नौकरी विवरण और आवेदन प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया सी-डॉट वेबसाइट के 'करियर' अनुभाग पर जाएँ:
https://www.cdot.in/cdotweb/web/careers.php?lang=en#current_openings

आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार (अंग्रेजी) में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर है। सभी सरकारी उम्मीदवारों को वेबसाइट में दिए गए विवरण के अनुसार उचित माध्यम से अपना आवेदन भेजना होगा।

cbc 06268/12/0005/2526

हस्ताक्षर/-
प्रमुख - कार्मिक एवं मानव संसाधन और कानूनी

सोमनाथ का रहस्य और अरब की देवी मनातः इतिहास और मिथक की जटिल कहानी

(जीएनएस)। गुजरात के समुद्र तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर आज सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, आस्था और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी का हमला और मंदिर की लूट ने भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में गहरी चोट छोड़ी, लेकिन आज 2026 में, एक हजार साल बाद, सोमनाथ मंदिर खड़ा है, और इसके प्रति श्रद्धा और गर्व की भावना लोगों के हृदय में उतनी ही प्रबल है। इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानी है—अरब की देवी मनात की मूर्ति को सोमनाथ में लाकर छिपा दिया गया था और महमूद गजनवी उसी मूर्ति को नष्ट करने के लिए आया था।

मनात या मनाह, इस्लाम से पहले के अरब की प्रमुख देवी मानी जाती थीं। इसका नाम अरबी शब्द 'मना' और 'मनिया' से आया माना जाता है, जिसका अर्थ भाग्य, नियति और किस्मत से जुड़ा हुआ है। मक्का में स्थित तीन प्रमुख देवियों—मनात, अल-लात और अल-उज्जा—में मनात को सबसे प्राचीन माना जाता था। इसका मंदिर लाल सागर के किनारे अल-मुशल्लल इलाके में स्थित था। इस्लाम के उदय के बाद, अरब में मूर्तियों और मंदिरों का विनाश शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार, साद बिन जैद अल-अश्हली को मनात की मूर्ति को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। इस दौरान यह कथा सामने आई कि मंदिर के पास से एक काली महिला प्रकट हुई, जिसे शयातीन या जिन्न के रूप में दर्शाया गया। मूर्ति और मंदिर नष्ट कर दिए गए और अरब की देवियों की परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो गई।

मध्यकालीन फारसी स्रोतों, विशेषकर कवि फर्रुखी सिस्तानी और अबू सईद गर्देजी, ने दावा किया कि मनात की मूर्ति को नष्ट न कर काठियावाड़ यानी वर्तमान गुजरात में सोमनाथ मंदिर में छिपा दिया गया। यही कथा धीरे-धीरे सोमनाथ को 'सु-मनात' या 'मनात का स्थान' बताकर फैलती गई। इस कहानी के अनुसार महमूद गजनवी का हमला सोमनाथ पर इसी मूर्ति को नष्ट करने

के लिए किया गया। पत्रकार और लेखक एम.जे. अकबर मानते हैं कि महमूद अपने अभियान को धार्मिक और राजनीतिक रूप से उचित ठहराने के लिए इस कथित विश्वास को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था।

लेकिन आधुनिक इतिहासकार, जैसे रोमिला थापर और कई अन्य विद्वान, इस कनेक्शन को मध्यकालीन फारसी कवियों और इतिहासकारों द्वारा गढ़ा गया प्रचार मानते हैं। भारतीय पुराण, मंदिरों की परंपरा और पुरातात्विक सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करते। सोमनाथ मंदिर प्राचीन काल से ही शिव मंदिर के रूप में स्थापित है, और अरब की देवी की मूर्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमले के पीछे तीन ठोस कारण बताए जाते हैं। पहला, दौलत और लूट। सोमनाथ मंदिर अत्यंत समृद्ध था, और महमूद ने इसे अपने दरबार, सेना और प्रशासनिक खर्चों के लिए लूटा। फारसी स्रोतों के अनुसार मंदिर का खजाना लाखों दिनार, सोने और चांदी से भरा था। दूसरा, राजनीतिक दबदबा। हाई-प्रोफाइल और समृद्ध मंदिर पर हमला करके महमूद ने हिंदू राजाओं और व्यापारिक समाज के मनोबल पर वार किया। तीसरा, धार्मिक आइकनोक्लाज़्म। महत्वपूर्ण मूर्ति-स्थलों को नष्ट करके महमूद ने सुन्नी इस्लाम के अपने निष्ठावान योद्धा और खलीफा के आदर्श प्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि बनाई। मनात वाली कहानी इस ऐतिहासिक घटना को धार्मिक और वैचारिक दृष्टि से जोड़ने का प्रयास मात्र प्रतीत होती है। असली गेम दौलत, शक्ति और राजनीतिक संदेश का था। अरब देवी की मूर्ति सोमनाथ में लाए जाने का कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। यह कहानी मध्यकालीन फारसी कवियों और इतिहासकारों द्वारा महमूद गजनवी की छवि को धार्मिक और राजनीतिक रूप से सही ठहराने के लिए गढ़ी गई प्रतीत होती है।

आज 2026 में सोमनाथ मंदिर हजार साल बाद भी खड़ा है। स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और 1955 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ एक मंदिर की मरम्मत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक है।

सोमनाथ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास और आस्था का मेल हमेशा सरल नहीं होता। मिथक, लोककथाएं और मध्यकालीन कवियों द्वारा बनाई गई कथाएं हमारी समझ को चुनौती देती हैं। अरब देवी मनात और सोमनाथ कनेक्शन की कहानी मध्यकालीन प्रचार का हिस्सा थी, लेकिन असली ऐतिहासिक तथ्य यह है कि महमूद गजनवी का हमला दौलत, शक्ति और राजनीतिक संदेश से प्रेरित था। आज सोमनाथ मंदिर, चाहे कितनी भी बार टूटा और बना, भारतीय संस्कृति, आस्था और सभ्यता का मजबूत प्रतीक है। हजार साल की मार, लूट और संघर्ष के बावजूद यह मंदिर खड़ा है और अपने आप में इतिहास पर समाज की जीत का प्रतीक बन गया है। सोमनाथ और मनात की कहानी यह याद दिलाती है कि असली इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज की आस्था, संघर्ष और स्मृति का प्रतीक भी है।

मिथक बनाम इतिहास के इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ कथा और प्रचार के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। मनात की कहानी रोमांचक और रहस्यमयी है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों और शोध के आधार पर इसे मध्यकालीन प्रचार माना जा सकता है। सोमनाथ की असली कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और परंपरा समय की कसौटी पर टिकती है, और मिथक केवल इतिहास की रंगीन पृष्ठभूमि बनकर रह जाते हैं।

योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसलाः पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण हुआ आसान, स्टाम्प शुल्क में मिली बड़ी राहत

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पारिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क छूट के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब यह राहत केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर भी लागू होगी। इस फैसले से पूर्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत परिवार के सदस्यों को दान में दी गई अचल संपत्ति के लिए संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। हालांकि 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना में पारिवारिक सदस्यों के लिए यह सुविधा दी गई थी कि दान की गई अचल संपत्ति पर अधिकतम 5,000 रुपये ही स्टाम्प शुल्क देना होगा, लेकिन यह केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। योगी कैबिनेट के ताजा फैसले से अब यह सुविधा व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों तक भी विस्तारित हो गई है, जिससे पारिवारिक संपत्ति का वैधानिक हस्तांतरण अब कहीं

भी, चाहे शहर हो या गांव, सरल और पारदर्शी बन गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि पहले पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण पर सर्किल रेट के अनुसार सात प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। इस निर्णय से आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही संपत्ति के वैध हस्तांतरण में भी आसानी आएगी। उनका कहना है कि यह कदम न केवल पारिवारिक विवादों को कम करेगा बल्कि संपत्ति के दान और हस्तांतरण को विवादमुक्त और पारदर्शी बनाएगा।

कैबिनेट ने इस फैसले के साथ ही स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसमें कुशीनगर के कप्तानगंज और झांसी में उप निबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई, जिस पर स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली-2025 को भी मंजूरी दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल पारिवारिक संपत्ति के दान और हस्तांतरण को सरल बनाता है बल्कि राज्य में व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता लाएगा। इससे नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और विवादमुक्त बनाना संभव होगा।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में यह राहत आम परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक सुविधा साबित होगी। इससे संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण में समय की बचत और विवादों की संभावना कम होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में पारिवारिक संपत्ति के कानूनी विवादों में कमी आएगी और नागरिकों के लिए संपत्ति का वैध हस्तांतरण आसान होगा।

योगी कैबिनेट के इस फैसले को जनहित में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल पारिवारिक संपत्ति का दान और हस्तांतरण सरल होगा बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों की प्रशासनिक प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी बन जाएगी। नागरिकों को अब संपत्ति हस्तांतरण के दौरान जटिल और महंगे स्टाम्प शुल्क की चिंता नहीं रहेगी।

इस फैसले के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति के दान और हस्तांतरण के मामले न केवल सरल होंगे बल्कि इससे राज्य में संपत्ति के वैध रिकॉर्ड का निर्माण और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय राज्य की प्रशासनिक दक्षता और नागरिक केंद्रित नीतियों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट का यह कदम पारिवारिक और व्यावसायिक संपत्तियों के दान व हस्तांतरण को आसान बनाने, आर्थिक राहत देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय न केवल वर्तमान नागरिकों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में संपत्ति संबंधी मामलों में विवादों और जटिलताओं की संभावना कम होगी।

एयर इंडिया की कमान बदलने की तैयारी में टाटा समूह, कैंपबेल विल्सन की हो सकती है विदाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। टाटा समूह ने देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया के नेतृत्व में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार समूह ने एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की तलाश शुरू कर दी है। मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 2027 में समाप्त होने वाला है, लेकिन जानकारी के अनुसार टाटा समूह ने इस पद पर जल्द ही बदलाव करने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है।

पिछले वर्ष जून में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद से ही कंपनी पर टाटा समूह की नजर बनी हुई है। हादसे के बाद संचालन, सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा के तहत टाटा समूह ने एयरलाइन की रणनीति और नेतृत्व को लेकर कई विकल्पों पर गौर किया है। अधिकारियों का कहना है कि समूह का मानना है कि नए नेतृत्व के जरिए एयरलाइन के संचालन, वित्तीय स्थिरता और ग्राहक सेवा के मानकों को और बेहतर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक टाटा समूह न केवल एयर इंडिया के सीईओ पद पर बदलाव करने पर विचार कर रहा है, बल्कि अपनी अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी नए प्रबंध निदेशक (एमडी) की नियुक्ति की संभावनाओं का विश्लेषण कर

रहा है। वर्तमान में इस पद पर आलोक सिंह कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल भी 2027 में समाप्त होने वाला है। विमान हादसे और उसके बाद कंपनी पर पड़े व्यापक प्रभाव, निजीकरण के बावजूद एयरलाइन की कमजोर वित्तीय स्थिति और संचालन संबंधी चुनौतियों को नेतृत्व परिवर्तन की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इस पद के लिए देश-विदेश के कई अनुभवी एयरलाइन अधिकारियों से बातचीत की है। इसका मकसद केवल किसी योग्य उम्मीदवार को नियुक्त करना नहीं बल्कि कंपनी की कार्यप्रणाली, वित्तीय स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उसे मजबूत बनाना भी है।

स्रोतों का कहना है कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट जून के आसपास आने की संभावना है। इस रिपोर्ट के परिणामों और उसमें सुझाए गए सुधारों के आधार पर भी नए नेतृत्व के लिए समय और प्रक्रिया तय की जा सकती है। इसके पहले, कैंपबेल विल्सन सोमवार को एक पूर्व निर्धारित बैठक में टाटा हाउस पहुंचे थे, जिसमें एयरलाइन के संचालन और सुधारात्मक कदमों पर चर्चा की गई।

कैंपबेल विल्सन को जुलाई 2022 में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया था। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में भारत सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। तब से लेकर अब तक एयरलाइन ने कई बड़े बदलाव देखे हैं, जिसमें नए विमानों का शामिल होना, अंतरराष्ट्रीय रूट्स का विस्तार और संचालन के डिजिटलाइजेशन पर जोर शामिल है। लेकिन विमान हादसे और उसके बाद की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंपनी को नई रणनीति और नए नेतृत्व की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एयरलाइन उद्योग में तेज़ी से बदलते माहौल, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सुरक्षा मानकों के कड़े होने के कारण किसी भी कंपनी को लगातार प्रबंधन और रणनीति पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में टाटा समूह का यह कदम न केवल एयर इंडिया की वित्तीय और संचालन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह निवेशकों और ग्राहकों को भी विश्वास दिलाने वाला है कि एयर इंडिया अब और अधिक पेशेवर, सुरक्षित और आधुनिक ढंग से संचालित होगी।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नए सीईओ की नियुक्ति कब होगी और क्या कैंपबेल विल्सन खुद इस पद से इस्तीफा देंगे या समूह उन्हें नए कार्यकाल तक बनाए रखेगा। लेकिन उद्योग विशेषज्ञ मान रहे हैं कि किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन एयरलाइन के लिए सकारात्मक संकेत होगा। यह कदम टाटा समूह के उस दृष्टिकोण को भी दिखाता है कि कंपनी के भीतर किसी भी तरह की चूक या सुरक्षा संबंधी जोखिम को गंभीरता से लिया जाएगा और उसके सुधार के लिए उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे।

टाटा समूह के लिए एयर इंडिया केवल एक व्यापारिक इकाई नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरराष्ट्रीय विमानन छवि और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में उसकी भूमिका का प्रतीक भी है। ऐसे में नए नेतृत्व की नियुक्ति न केवल परिचालन और वित्तीय सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एयरलाइन की रणनीतिक दिशा और लंबी अवधि की योजनाओं में भी बदलाव ला सकती है।

कैट आयोजित करेगा 'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026', भारत मंडपम में होगा व्यापारियों का मेला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के कारोबारी और उद्यमियों के लिए आगामी साल की सबसे बड़ी व्यापारिक पहल आने वाली है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 1 से 4 मई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चार दिवसीय 'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026' का आयोजन करेगा। यह महोत्सव केवल एक व्यापार प्रदर्शन नहीं बल्कि भारतीय व्यापार की ताकत, स्थानीय उद्योगों की प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह महोत्सव 'आत्मनिर्भर भारत', 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलते माहौल, बढ़ते टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आए भू-राजनीतिक तनावों के बीच यह आयोजन भारत के लिए नए अवसर पैदा करेगा। व्यापार महोत्सव 2026 देश का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो होगा और इसे 'वन नेशन–वन मार्केट' की अवधारणा को मजबूत करने वाला भी माना जा रहा है।

खंडेलवाल ने बताया कि इस महोत्सव का आधार 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड' होगा। इसमें देशभर के 2,000 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगेंगे और अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा व्यापारी और करीब 10 लाख आगंतुक इस आयोजन का हिस्सा होंगे। इस दौरान बड़े पैमाने पर व्यापारिक सौदे, साझेदारियां, निवेश के अवसर और नए व्यवसायिक नेटवर्किंग के मौके सामने आएंगे।

इस महोत्सव में छोटे और मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला और युवा उद्यमी, स्टार्टअप्स, कारीगर, स्वयं सहायता समूह और पारंपरिक उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजकों ने इसे केवल एक प्रदर्शनी के रूप में नहीं देखा है बल्कि इसे राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर भारतीय व्यापार को नई पहचान देने वाला एक मेगा व्यापार उत्सव बताया गया है। प्रदर्शनी को आठ प्रमुख जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें बी2बी जोन, निवेश एवं वित्त, हस्तशिल्प, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास और 'टेस्ट्स ऑफ इंडिया' शामिल हैं।

खंडेलवाल ने यह भी कहा कि महोत्सव का उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि स्थानीय उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना भी है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और तकनीकी नवाचारों के लिए भी विशेष स्थान रखा गया है ताकि छोटे और मध्यम उद्योग अपनी पहुंच को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में सरकार, निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों का सहयोग होगा और यह भारतीय व्यापार की शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर साबित होगा।

व्यापार महोत्सव में निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए अलग सेक्शन तैयार किया गया है, जहां वे नई टेक्नोलॉजी, उत्पाद और सेवाओं के साथ सीधे निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा, महिला और युवा उद्यमियों के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे उन्हें नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग के अवसर मिल सकें।

इस महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत के कारोबारी और उद्योग जगत अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी खुद को साबित कर सकते हैं। कैट ने इस आयोजन के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया है कि 'आत्मनिर्भर भारत' केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविकता में व्यापारिक सामर्थ्य और स्थानीय उत्पादन को वैश्विक मंच पर ले जाने का अभियान है।

इस तरह 'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026' न केवल भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए बल्कि पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह महोत्सव न सिर्फ व्यापारियों और निवेशकों के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगा, बल्कि आम जनता को भी यह संदेश देगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और इसकी नींव मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है।

ऑस्कर की दौड़ में भारत का मान बढ़ाया 'होमबाउंड', 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जगह

(जीएनएस)। लॉस एंजेल्स। भारतीय सिनेमा के लिए ऑस्कर 2026 की रेस में एक और बड़ा मुकाम हासिल हो गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में अगले वोटिंग राउंड तक पहुँच गई है। इस राउंड में अब केवल 15 फिल्मों को शामिल किया गया है, जो कि विश्वभर की श्रेष्ठ और चर्चित फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। ऑस्कर की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार 22 जनवरी को नॉमिनेशन की घोषणा की जाएगी और इसके बाद 15 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 के भव्य समारोह में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। निर्देशक नीरज घेवान की यह फिल्म भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह केवल पाँचवीं फिल्म है जिसे ऑस्कर की अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे पहले भारतीय फिल्में 'बैंडिट क्वीन', 'लंचबॉक्स', 'पीके' और 'दंगाल' जैसी चर्चित कृतियाँ इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुई थीं। 'होमबाउंड' की शॉर्टलिस्टिंग भारतीय फिल्म उद्योग की वैश्विक पहचान और गुणवत्ता की पुष्टि करती है। 'होमबाउंड' की कहानी दो दोस्तों के जीवन संघर्ष, उनके सपनों और सामाजिक बाधाओं से ऊपर उठने की कोशिश को केंद्र में रखती है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिनकी अभिनय प्रतिभा और कैमिस्ट्री को आलोचकों ने पहले ही सराहा है। फिल्म की पटकथा, निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी ने दर्शकों और अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों दोनों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा फिल्म की संगीत रचना और दृश्य प्रस्तुति ने इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दिया है। ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में पहुँचने के बाद नीरज घेवान और उनकी टीम ने कहा कि यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि फिल्म का मकसद केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को पर्दे पर लाना और आम दर्शकों को प्रेरित करना भी था। फिल्म में दिखाए गए दोस्ती, संघर्ष और नैतिक चुनौतियों के माध्यम से भारतीय समाज के विविध पहलुओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में इस राउंड में जगह बनाने वाली अन्य 14 फिल्में अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, जॉर्डन, नॉर्वे, फिलिस्तीन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ताइवान और ट्यूनीशिया से हैं। इस प्रतिस्पर्धा की उच्च स्तरीय प्रकृति को देखकर यह स्पष्ट है कि 'होमबाउंड' की सफलता केवल भारत के लिए गौरव की बात नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का संकेत भी है।

सोना वायदा में 309 रुपये और चांदी वायदा में 3811 रुपये की वृद्धिः क्रूड ऑयल वायदा में 17 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 129187.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 36349.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 92828.71 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 36098 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1987.73 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 27783.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138666 रुपये के भाव पर खूलकर, 138776 रुपये के दिन के उच्च और 138001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 138120 रुपये के पिछले बंद के सामने 309 रुपये या 0.22 फीसदी की बढ़त के साथ 138429 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 119 रुपये या 0.11 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 113265 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 20 रुपये या 0.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14163 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 138793 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138793 रुपये और नीचे में 137911 रुपये पर पहुंचकर, 344 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 138400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 138775 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 139400 रुपये और नीचे में 138775 रुपये पर पहुंचकर, 138619 रुपये के पिछले बंद के सामने 641 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 250450 रुपये के भाव पर खूलकर, 251050 रुपये के दिन के उच्च और 246888 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 246155 रुपये के पिछले बंद के सामने 3811 रुपये या 1.55 फीसदी की मजबूती के साथ 249966 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3604 रुपये या 1.45 फीसदी की तेजी के संग 251809 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3671 रुपये या 1.48 फीसदी बढ़कर 251859 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 36349.14 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 92828.71 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 27783.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36098 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 6442.29 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 11.55 रुपये या 0.88 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1324.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 3.85 रुपये या 1.24 फीसदी की तेजी के संग 314.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 5.4 रुपये या 1.76 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 311.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 4.95 रुपये या 2.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 189.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2293.44 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5256 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5304 रुपये और नीचे में 5230 रुपये पर पहुंचकर, 17 रुपये या 0.32 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5287 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 17 रुपये या 0.32 फीसदी की बढ़त के साथ 5287 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 313.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 314.8 रुपये के दिन के उच्च और 309 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 315.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.8 रुपये या 1.52 फीसदी लुढ़ककर 310.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5 रुपये या 1.59 फीसदी गिरकर 310.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 1007 रुपये पर खूलकर, 2.7 रुपये या 0.27 फीसदी औंधकर 1013 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11827.96 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15955.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5336.28 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 523.14 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 112.21 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 456.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 570.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1701.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19155 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 73795 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28125 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 422084 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 46589 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16299 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39259 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99736 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20842 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 46099 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 35751 पॉइंट पर खूलकर, 36169 के उच्च और 35751 के नीचले स्तर को छूकर, 205 पॉइंट बढ़कर 36098 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.2 रुपये की बढ़त के साथ 100.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.05 रुपये की गिरावट के साथ 21.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 22 रुपये की गिरावट के साथ 856.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 691.5 रुपये की बढ़त के साथ 10000 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.89 रुपये की गिरावट के साथ 63 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 73 पैसे की नरमी के साथ 6.55 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.9 रुपये की गिरावट के साथ 63.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2 रुपये की बढ़त के साथ 20.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 5.5 रुपये की गिरावट के साथ 415 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1228 रुपये की गिरावट के साथ 5550 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16.24 रुपये की गिरावट के साथ 37.02 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 3 रुपये हुआ।